

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23062023-246760  
SG-DL-E-23062023-246760असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2023/आषाढ 1, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 99
No. 183]	DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2023/ASHADHA 1, 1945	[N. C. T. D. No. 99

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जून, 2023

संख्या-09/2023-राज्य कर

सं. फा. 03(02)/वित्त (व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/548.-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03 ) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में सं. फा. 03(84)/वित्त (व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/288, तारीख 24 मार्च, 2021 में प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में सं. फा. 03(115)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/313, तारीख 17 नवंबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2021-राज्य कर, तथा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में सं.फा.03(22)/वित्त (व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/818, तारीख 12 अक्टूबर, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2022-राज्य कर, के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त किए गए या कम

संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करते हैं, अर्थात् :—

- (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसंबर, 2023 तक;
- (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक;
- (iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय- I)

### FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 22nd June, 2023

#### No. 09/2023-State Tax

**No. F. 3 (02)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/548.**—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and in partial modification of the notification of this Government issued vide Notification, No.35/2020-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No.F.3(84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/288, dated 24<sup>th</sup> March, 2021 and No. 14/2021-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3(115)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/313, dated 17<sup>th</sup> November, 2021 and No. 13/2022-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* No.F.3(22)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/818, dated 12<sup>th</sup> October, 2022, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below, namely:—

- (i) for the financial year 2017-18, up to the 31st day of December, 2023;
- (ii) for the financial year 2018-19, up to the 31st day of March, 2024;
- (iii) for the financial year 2019-20, up to the 30th day of June, 2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp. I)